
संपूर्ण

NCERT सार

भारतीय अर्थव्यवस्था

जनसंख्या एवं & नगरीकरण

वन लाइनर

कक्षा - VI - XII

प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण एवं आशीष गिरि

सम्पादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

फोन : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com/www.yctbooksprime.com

© All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने E:Book by APP YCT BOOKS, से मुद्रित करवाकर,
वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है
फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव सादर आमंत्रित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय सूची

भारतीय अर्थव्यवस्था

नीतिगत आयाम

■ राष्ट्रीय आय/बजट	3
■ राजस्व एवं राजकोषीय नीति/घाटा	12
■ मुद्रा एवं बैंकिंग/वित्तीय समावेशन की योजनाएँ	17
■ मुद्रास्फीति	36
■ पूँजी बाजार	40
■ भारतीय वित्तीय प्रणाली/वित्त आयोग	44
■ अवमूल्यन/कारोपण	45
■ आर्थिक नियोजन	47

आर्थिक आयाम

■ कृषि	57
■ उद्योग/औद्योगिक क्षेत्र	66
■ सेवा	70
■ खनिज संसाधन	70
■ ऊर्जा संसाधन	71
■ परिवहन एवं संचार	71

सामाजिक आयाम

■ गरीबी एवं बेरोजगारी	71
■ कृषि सम्बन्धी योजनाएँ	74
■ सतत् विकास की योजनाएँ	76
■ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाएँ	77
■ शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ	78
■ बुनियादी ढांचा एवं नवाचार क्षेत्र की योजनाएँ	79
■ महिला, वृद्ध एवं बाल कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ	80
■ गरीबी उन्मूलन और रोजगार कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ	82
■ अल्पसंख्यक, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ	87
■ अन्य योजनाएँ	87
■ महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक	89

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन

■ आयात-निर्यात की दशा एवं दिशा	91
■ भुगतान संतुलन एवं व्यापार समझौते	94
■ विदेशी निवेश एवं ऋण	96
■ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन	97
■ विविध	100

जनसंख्या एवं नगरीकरण

■ भारतीय जनसंख्या	115
■ भारतीय नगरीकरण	124
■ विश्व जनसंख्या)	126
■ विश्व नगरीकरण	127
■ विविध	127

भारतीय अर्थव्यवस्था

(Indian Economy)

नीतिगत आयाम (Policy Dimensions)

राष्ट्रीय आय/बजट

<p>■ भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था है— राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्व में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन)</p>	<p>UPSSSC PET 24/08/2021 Shift-II जूनियर इंजीनियर/तकनीकी- 31-07-2016 जूनियर इंजीनियर/तकनीकी - 27-12-2015 RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB Group-D 24-10-2018 (Shift-III) UPPCS (Pre) G.S. 1995 UPPCS (Pre) G.S. 2006 UPPCS (Main) G.S. Ist Paper 2010 UPPCS (Main) G.S. Ist Paper 2008 UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2006</p>
<p>■ स्वतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट पेश किया था— R.K. घणमुखम चेड़ी ने</p>	<p>RRB JE - 30/05/2019 (Shift-III)</p>
<p>■ भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है— 1964 के बाद से</p>	<p>RRB NTPC 03.03.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है— वार्षिक वित्तीय विवरण</p>	<p>RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-III) UPSI Batch-2, 22 Dec 2017 SSC CGL (Tier-1)– 17/07/2023 (Shift-II)</p>
<p>■ पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था— सी.डी.देशमुख द्वारा</p>	<p>SSC CGL (Tier-I) 21/04/2022 (Shift-I) SSC CGL (TIER-1) 27-10-2016, (Shift-I) SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-I) UPSI, 1999</p>
<p>■ किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है— व्यय विधि</p>	<p>SSC MTS/Havaladar–08/09/2023 (Shift-II)</p>
<p>■ सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है— पूँजी खपत भत्ता</p>	<p>UDA/LDA 29-11-2015</p>
<p>■ 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय थी— ₹249.60</p>	<p>कनिष्ठ सहायक - 19-02-2019</p>
<p>■ वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को घटकों में विभाजित किया गया है— तीन</p>	<p>UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-I</p>
<p>■ कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 2017 ने से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है— जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति उपकर</p>	<p>UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-I</p>
<p>■ एकीकृत कम लागत स्वच्छता (ILCS) योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है— 75%</p>	<p>UPSSSC Homeopathic Pharmacist 24/10/2019</p>
<p>■ वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर (गुडस एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है— 28%</p>	<p>Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-II)</p>
<p>■ सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली (HS) के लिए लाभकारी होगी— सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण</p>	<p>UDA/LDA 29-11-2015</p>
<p>■ भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है— राज्य सरकारों द्वारा</p>	<p>लोअर प्रथम- 28-02-2016</p>
<p>■ भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है— सेवा कर</p>	<p>आबकारी सिपाही - 25-09-2016</p>

■ भारत में आयकर को कहा जा सकता है-	प्रत्यक्ष और प्रगामी	UDA/LDA 29-11-2015
■ प्रत्याशित समग्र मांग (Ex Ante Aggregate Demand) की गणना के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है-	$\bar{C} + \bar{I} + cY$	RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-I)
■ मैक्रोइकॉनॉमिक्स (समष्टि अर्थशास्त्र) विश्लेषण में उपभोग फलन (consumption function), कुल उपभोग और के बीच संबंध का वर्णन करता है-	सकल राष्ट्रीय आय	RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-II)
■ वह उत्पादन चक्र कहलाता है, जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है-	अल्पावधि उत्पादन (short run production)	RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-I)
■ उत्पादन की सीमांत लागत, अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है-	1	RRB Group-D – 13/09/2022 (Shift-II)
■ उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्व-स्वामित्व वाले आगतों (inputs) की लागत का अभिप्राय है-	अंतर्निहित लागत (Implicit cost)	RRB Group- D – 11/10/2022 (Shift-II)
■ एक फर्म का उत्पादन फलन, उपयोग में लाए गए आगतों और के मध्य का संबंध है-	फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों	RRB Group- D – 11/10/2022 (Shift-II)
■ किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है-	जनसंख्या वृद्धि	RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-I)
■ समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण (macroeconomic analysis) में, सीमांत बचत प्रवृत्ति (MPS) दर्शाती है-	किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन	RRB Group- D – 28/09/2022 (Shift-III)
■ आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत (ex-ante consumption) में वृद्धि की दर कहलाती है-	सीमांत उपभोग प्रवृत्ति	RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-II)
■ किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ (उपयोगिता) को कहा जाता है-	सीमांत उपयोगिता	RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-II)
■ अर्थशास्त्र में, कुल परिवर्तनीय लागत ÷ उत्पादित उत्पादन की इकाइयां =	औसत परिवर्तनीय लागत	RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-I)
■ अनधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है-	प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा	RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-II)
■ यदि औसत उत्पादन घट रहा है, तो सीमांत उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा— यह औसत उत्पादन से कम होगा		RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-III)
■ जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है, तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा—	धनात्मक	RRB Group-D – 30/08/2022 (Shift-III)
■ जब तक MP (सीमांत उत्पाद), औसत उत्पाद (AP) से अधिक रहता है, तब तक औसत उत्पाद— बढ़ना जारी रहता है		RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-I)
■ किसी वस्तु की वह मात्रा, जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, सुचियों और अनधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है, और क्षमता रखता है, को उस वस्तु की कहते हैं—	मांग	RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-II)
■ अर्थशास्त्र में, औसत उत्पाद =	कुल उत्पाद ÷ श्रम	RRB Group-D – 14/09/2022 (Shift-II)
■ औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को कहा जाता है— औसत लागत		RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-II)
■ यह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है—	सुनिश्चित लागत (explicit cost)	RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-III)
■ वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है—	संतुलन कीमत	RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-III)
■ स्थिर पैमाना का प्रतिफल (CRS) उत्पादन फलन की एक विशेषता है, यह तब होता है, जब— सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है		RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-I)

■ उत्पादन के चार कारक हैं-	भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यमिता	RRB Group-D – 11/10/2022 (Shift-III)
■ अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होती है-	औसत परिवर्ती लागत + औसत नियत लागत	RRB Group-D – 06/10/2022 (Shift-III)
■ उत्पाद के चरण में, सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है-	चरण 2	RRB Group-D – 08/09/2022 (Shift-I)
■ परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है-	औसत उत्पाद को	RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)
■ इस उत्पादन फलन में, उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं-	दीर्घकालीन उत्पादन फलन	RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift-II)
■ पूर्ति वक्र (supply curve) पर वह बिंदु, जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है, कहलाता है-	ब्रेक-इवेन बिंदु	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-III)
■ मांग वक्र लोचदार होता है और होने पर यह बेलोचदार होता है-	सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर; सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-I)
■ किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है-	मांग की कीमत लोच	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-I)
■ वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी-	कीन्सियन गुणक	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-II)
■ निवल मूल्य (नेट वर्थ) का सूत्र है-	निवल मूल्य = परिसंपत्तियां – देयताएं	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-II)
■ आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले इनपुट को जाना जाता है-	उत्पादन के घटक के रूप में	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-I)
■ किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है-	यथार्थ प्रेरक	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-I)
■ के कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र 'U'- आकृति का होना है-	परिवर्ती अनुपात के नियम	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-I)
■ अर्थशास्त्र में एक वक्र होता है, जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर, उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं-	संयोजक	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-III)
■ जब सभी इनपुट में आनुपातिक वृद्धि के परिणामस्वरूप आउटपुट में बढ़े अनुपात में वृद्धि होती है, तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है-	पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-II)
■ चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है-	औसत उत्पाद को	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-I)
■ खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है-	उपभोग वस्तुएं	RRB NTPC 10.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गयी ऊपरी सीमा को कहा जाता है-	अन्तिम सीमा मूल्य	RRB NTPC 10.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किये गये वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं-	उपभोक्ता अधिशेष	RRB NTPC Stage I ^t 30.04.2016 (Shift-III)
■ जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है-	शून्य	RRB NTPC Stage I ^t 30.04.2016 (Shift-III)
■ गिफिन वस्तुओं का सम्बन्ध है-	आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ एक अर्थव्यवस्था में पूँजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूँजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रूप में व्यक्त किया जाता है-	शुद्ध निवेश = सकल निवेश - मूल्यहास	RRB NTPC 05.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है-	कुल लागत के रूप में	RRB NTPC 12.01.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से जानी जाती है—	औसत लागत	RRB NTPC 05.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ हासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार, जैसे-जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता—	हासित होती है	RRB NTPC 21.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी—	अल्पविकसित और रुद्ध	RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-II)
■ अर्थव्यवस्था के आकार (size) के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप है—	सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	RRB Group-D : 30/08/2022 (Shift-I)
■ स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, भारत का सकल घरेलू उत्पाद था—	₹2.7 लाख करोड़	RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-I)
■ वह धन है, जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है—	प्रयोज्य आय	RRB Group-D – 22/08/2022 (Shift-III)
■ जब हम NNP (निवल राष्ट्रीय उत्पाद) को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तो हमें प्राप्त होती है—	प्रति व्यक्ति आय	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-I)
■ साम्य राष्ट्रीय आय (Equilibrium national income) तब होती है जब समग्र आपूर्ति— समग्र मांग के बराबर होती है		RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-III)
■ आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक..... में निरंतर वृद्धि है—	जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट)	RRB NTPC 09.01.2021 (Shift-II) Stage Ist SSC MTS– 16/05/2023 (Shift-II) SSC MTS 9-10-2017 (Shift-II) UPP Com. Operator. 19-05-2016 (Shift-II) SSC JE Civil - 24/01/2018 (Shift-I)
■ हमें सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि—	तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है	RRB NTPC 24.07.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ 'हिंदू वृद्धि दर' नामक शब्दने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है—	राज कृष्ण	RRB NTPC 23.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ वह क्षेत्र जो भारत की जीडीपी (GDP) में सर्वाधिक योगदान देता है—	तृतीयक क्षेत्र	RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product) से अवमूल्यन (depreciation) घटाने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है—	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ नेट नेशनल प्रोडक्ट (NNP) है—	NNP = GNP – Depreciation (मूल्यहास)	RRB NTPC 28.12.2020 (Shift-II) Stage Ist SSC CGL (Tier-1) – 21/07/2023 (Shift-II)
■ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था—	दादाभाई नौरोजी ने	RRB NTPC 28.12.2020 (Shift-II) Stage Ist
■ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक निश्चित अवधि के दौरान का कुल मूल्य है—	एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और दी गई सेवाओं	RRB NTPC Stage 1 st 19.01.2017 (Shift-II)
■ अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप है—	नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट	RRB JE - 27/06/2019 (Shift-III)
■ भारत में राष्ट्रीय आय कोके पदों में मापा जाता है—	बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	RRB JE - 22/05/2019 (Shift-III)
■ सरकारी बजट में, जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं, तो आय और व्यय के बीच अंतर को कहा जाता है—	बजट घाटा	RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-I)
■ 2022 – 23 के सरकारी बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 – 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर है—	9.2%	RRB Group-D – 13/09/2022 (Shift-III) RRB Group- D – 11/10/2022 (Shift-I) RRB Group- D – 14/09/2022 (Shift-I)
■ भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है—	साख नियंत्रण	RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-I)
■ अर्थशास्त्र में, 'बजट अधिशेष (Budget Surplus) का अर्थ है—	जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो	RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I)

■ जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे कहा जाता है— सार्वजनिक व्यवस्था	RRB NTPC 12.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वित्तीय वर्ष को बदल कर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य है— मध्य प्रदेश	RRB Group-D 12-10-2018 (Shift-II)
■ वित्तीय वर्ष से लम्बित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किये गये अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है— लेखानुदान	RRB NTPC Stage I st 27.04.2016 (Shift-II)
■ केन्द्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित विलय वर्ष किया गया— 2017-18	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-II) Stage II nd
■ संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना इन दोनों को संतुलित करने को कहा जाता है— सतत विकास	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ आय के पांच मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहा जाता है— सकल कुल आय	UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठन किया गया था— राष्ट्रीय विकास परिषद का	UPSI Batch-3, 22 Dec 2017
■ वह संकेतक जो आय की असमानता/ समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है— गिनी गुणांक	UPSI Batch-1, 21 Dec 2017
■ एक अर्थव्यवस्था, यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण होगा— सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
■ वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही कथन है— किसी चुनाव वर्ष, में बजट दो बार पेश किया जा सकता है- पहली बार, लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017
■ वह बजट जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए है— शून्य आधारित बजट	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017
■ रेल बजट के संदर्भ में सही कथन हैं— 1. भारतीय रेल का बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है (वर्ष 2015 तक) 2. प्राप्तियाँ और व्यय से जुड़ी राशि 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा बजट में जोड़ी जाती हैं 3. रेल की प्राप्तियाँ और व्यय, भारत की समेकित निधि का हिस्सा है	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है— भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा	UPP Com. Operator. (Grade-A), 2013 UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I राजस्व निरीक्षक - 17-07-2016 (Paper-I)
■ भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है— जनसंख्या वृद्धि के कारण	UPP Com. Operator. (Grade-A), 2013
■ प्राथमिक घाटा को मापा जाता है— राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान	UPPCS (J) 2023
■ भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है— सेवा क्षेत्र	UPPCS RO/ARO (Pre) 2021
■ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है। वह श्रेणी है— आय निर्धनता, मानव निर्धनता	UPPCS (Pre) Exam 2022
■ भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है— सीमा शुल्क	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper-I
■ केन्द्रीय सरकार की पूँजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है— कर प्राप्तियाँ	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ आर्थिक क्रिया नहीं है— स्वेच्छिक समाज सेवा	UPPCS (Pre) 2023
■ बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी— वर्ष 1996-97 में	UPPCS (Pre.) G.S. 2002

■ प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय, वर्ष 2004-05 में सबसे कम थी— (वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा 502425 रु. जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार 47,541 रु. की है)	बिहार में 2011-12	UPPCS (Pre) G.S. 2008 UP Lower (Pre) -2003 UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2011 UPPCS (Pre) G.S. 1994
■ इस समय (2015) से भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है—	घरेलू क्षेत्र	UPPCS (Main) G.S. Ist 2016 UPPCS (Main) G.S. Ist 2004 UP UDA/LDA Spl. (Pre) G.S. 2010
■ भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है—	घरेलू क्षेत्र	UPPCS (Pre.) G.S. 2003 UPPcS (Main) G.S. IIInd 2004
■ भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केन्द्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है— योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है।)		UPPCS (Pre) G.S. 2014
■ आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी— केलकर कमेटी ने		UPPCS (Main) Spl. G.S. Ist Paper 2008
■ भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया— दादाभाई नौरोजी द्वारा		UPPcS (Pre) G.S. 2007
■ आर्थिक नियोजन के युग में आरम्भ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा— पहले बढ़ा फिर कम हुआ है		UPPCS (Pre.) G.S. 1999
■ “मार्केट कैप” का परिमाण उसके जी.डी.पी. से अधिक है— यू.एस.ए. की		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2009
■ GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) में श्रम की भागीदारी कम है— कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
■ राष्ट्र की सम्पदा में शामिल नहीं किया जाता है— मुद्रा-पूर्ति		UPPCS (Main) Spl. G.S. IIInd 2004
■ यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाएँ तो वास्तविक आय—		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2004
■ भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में है— 1.09 प्रतिशत (वर्ष 2022-23 में 2.1 प्रतिशत)		UP RO/ARO (Pre) G.S. 2013
■ पेमेन्ट ऑफ ब्रैच्युटी ऐक्ट, 1972 के अनुसार ब्रैच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा है— रु. 10 लाख (वर्तमान में रु. 20 लाख)		UP RO/ARO (Pre) G.S., 2014
■ भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है— उपभोक्ता मूल्य सूचकांक		UP Lower (Pre.) G.S. 2008
■ भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की है— 2006-07 में		UPPCS (Pre) G.S. 2008 UP RO/ARO (M) G.S. 2013
■ आयकर विभाग द्वारा जारी PAN कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता है— पते का प्रमाण		UPPCS (Pre) G.S. 2007
■ समानांतर अर्थव्यवस्था.....के कारण उभरती है— कर वंचन		SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift-II)
■ आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात, जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी, ---- के रूप में जाना जाता है—		SSC CHSL 31/05/2022 (Shift-III)
■ उपादान भुगतान प्रवाह का, कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है— आय वितरण कोण		SSC CHSL 30/05/2022 (Shift-II)
■ सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं— डेविड रिकार्डों		SSC CGL (Tier-I) 12/04/2022 (Shift-I)
■ टपकन सिद्धांत (आपमात्रीय सिद्धांत) निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजर अंदाज करता है— आय वितरण		SSC CGL (TIER-1) 27-08-2016, 10am
■ वैयक्तिक आयकरों की कटौती से पहले सभी स्त्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है— वैयक्तिक आय		SSC CGL Mains -26/10/2023 (Shift-I)
■ राष्ट्रीय आय की गणना में, निम्न मदों में बाजार मूल्य पर एनएनपी (NNP) में से घटाया जाएगा— निवल अप्रत्यक्ष कर		SSC CHSL (Tier-1) – 09/08/2023 (Shift-I) (SSC J.E. 02.03.17, 10:00 am)

■ शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है— जी.डी.पी. – मूल्यहास	(SSC 10+2 CHSL 07.01.17, 10 am) SSC CHSL (Tier-I) –08/07/2019 (Shift-I) SSC MTS 18/10/2021 (Shift-I) SSC MTS 14/10/2021 (Shift-I)
■ 1950-51 में, सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग प्रतिशत था— 11.8	SSC GD – 01/02/2023 (Shift-II) SSC CGL (TIER-1) 10-09-2016, 4.15 pm
■ राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं/सेवाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि— यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है	SSC MTS/Havaladar–05/09/2023 (Shift-III)
■ यह राष्ट्रीय आय को मापने की व्यविधि का उचित रूप से कथित घटक नहीं है— निर्यात और आयात व्यय	SSC CHSL (Tier-I) – 07/08/2023 (Shift-IV)
■ राष्ट्रीय आय का व्यापक संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है— कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद - कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद - वैयक्तिक आय - वैयक्तिक प्रयोज्य आय	SSC CHSL (Tier-I) – 07/08/2023 (Shift-IV)
■ निवल आर्थिक कल्याण (NEW) की गणना करते समय, निम्न मदों में जीएनपी (GNP) में से घटाया जाता है— शहरी जीवन की भीड़ के समायोजन	SSC CHSL (Tier-I) – 14/08/2023 (Shift-IV)
■ एमपी (MP) पर जीएनपी (GNP) में से _____ घटाने पर हमें एमपी (MP) पर जीडीपी (GDP) प्राप्त होती है— विदेश से निवल कारक आय	
■ समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला संकेतक है— प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद	SSC CHSL (Tier-I) – 17/08/2023 (Shift-II)
■ यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तु व सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का माप मिलता है। यह अनुमान कहलाता है— सकल घरेलू उत्पाद	SSC MTS– 11/05/2023 (Shift-II)
■ आटे में गेहूँ का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि का एक भाग है— मूल्यवर्धित	SSC CHSL (Tier-I) – 04/08/2023 (Shift-III)
■ जी. डी. पी. अपस्कीतिकारक (GDP डिफलेटर)— सांकेतिक जी. डी. पी. (GDP) / वास्तविक जी. डी. पी. (GDP) ×100	SSC CGL (Tier-I)– 18/07/2023 (Shift-III)
■ 2022 की स्थिति के अनुसार, भारत दुनियां की.....सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (नाममात्र जीडीपी (nominal GDP) द्वारा मापा गया)– पाँचवाँ	SSC CHSL (Tier-I) – 10/03/2023 (Shift-II)
■ किसी भी अर्थव्यवस्था में, जनता द्वारा संचित धन (निष्क्रिय) का आय वेग के बराबर होता है— शून्य	SSC CHSL (Tier-I) – 03/08/2023 (Shift-IV)
■ किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न मापदंड है— प्रति व्यक्ति आय	SSC GD 14/02/2019 (Shift-II)
■ एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है— GSDP	SSC JE Civil 28.10.2020 (Shift-II)
■ विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड है— प्रति व्यक्ति आय	SSC GD 02/12/2021 (Shift-II)
■ G.V.A. अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। G.V.A. का पूर्ण स्वरूप है— ग्रॉस वैल्यू एडेड	SSC GD 10/12/2021 (Shift-II)
■ राज्य की आय, जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, कहलाती है— राजगामित्व	SSC CHSL 08/06/2022 (Shift-I)
■ यह अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर-आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए— सकल राष्ट्रीय खुशहाली	SSC MTS 05/10/2021 (Shift-I)
■ एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना तीन विधियों द्वारा की जा सकती है: आय विधि, व्यय विधि और— उत्पाद/मूल्य वर्धित विधि	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 05/03/2020 (Shift-II)

■ औसत आय को कहा जाता है-	प्रति व्यक्ति आय	SSC MTS 10-10-2017 (Shift-I) SSC CGL 08-09-2016, 10 am SSC MTS 10-10-2017 (Shift-II) SSC CGL (TIER-1) 03-09-2016, 4.15 pm SSC CGL (TIER-1) 04-09-2016, 10 am
■ देश के सभी निवासियों की आय कहलाती है-	कुल आय	SSC MTS 9-10-2017 (Shift-I)
■ GNP का अर्थ है-	ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 09/03/2020 (Shift-I) (SSC J.E. 04.03.17, 10:00 am) (SSC J.E. 02.03.17, 2:45 pm)
■ कम्पनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है-	सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि	SSC CGL (Tier-I) – 13/06/2019 (Shift-I)
■ निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर – (अप्रत्यक्ष कर – उपदान)–	राष्ट्रीय आय	(SSC J.E. 01.03.17, 10:00 am)
■ वैयक्तिक प्रयोज्य आय-	वैयक्तिक आय–वैयक्तिक कर अदायगी–गैरकर अदायगी	(SSC J.E. 04.03.17, 2:45 pm) (SSC 10+2 CHSL 19.01.17, 1.15 pm) SSC CGL (TIER-1) 06-09-2016, 10 am (SSC J.E. 04.03.17, 2:45 pm)
■ राष्ट्रीय आय–अवितरित लाभ–परिवारों द्वारा की गयी निवल व्याज आदयगी–निगम कर + सरकार और फर्मों से परिवारों को की गयी अंतरण अदायगी कहलाती है–	वैयक्तिक आय	(SSC J.E. 03.03.17, 10:00 am)
■ भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है–	सकल घरेलू उत्पाद	SSC JE Mechanical 27.10.2020 (Shift-I)
■ राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न गणना नहीं की जाती है–	गृहिणी की सेवाएँ	SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift-II)
■ भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं–	वी. के. आर. वी. राव	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-II)
■ अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से आशय है–	पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु	SSC CGL (Tier-I) – 10/06/2019 (Shift-III)
■ वित्तीय वर्ष (fiscal year) है–	सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष	SSC MTS/Havaldar-04/09/2023 (Shift-II) SSC CHSL (Tier-1) – 03/08/2023 (Shift-II) SSC CGL (Tier-1) – 25/07/2023 (Shift-IV) SSC CHSL (Tier-1) – 14/08/2023 (Shift-II) SSC MTS/Havaldar- 05/07/2022 (Shift-I)
■ सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है–	राजकोषीय घटा	SSC CHSL (Tier-1) – 03/08/2023 (Shift-II)
■ वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार, सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति में कोर्पोरेशन टैक्स (Corporation tax) होता है–	15 पैसे	SSC MTS- 02/05/2023 (Shift-I)
■ सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है–	सरकार द्वारा संग्रहित जी.एस.टी. (GST)	SSC CGL (Tier-1) – 26/07/2023 (Shift-III)
■ निम्न राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार ‘चाइल्ड बजट’ प्रस्तुत किया–	मध्य प्रदेश	SSC CGL (Tier-1) – 25/07/2023 (Shift-IV)
■ केंद्रीय बजट में ‘राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF)’ नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी–	2015-16	SSC CGL (Tier-1) – 20/07/2023 (Shift-IV)
■ केंद्रीय बजट 2022-24 में, भारत सरकार ने सात प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें कहा जाता है–	सप्तऋषि	SSC CHSL (Tier-1) – 08/08/2023 (Shift-IV)
■ भारत सरकार ने FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) अधिनियम लागू किया–	2004-05	SSC CHSL (Tier-1) – 08/08/2023 (Shift-IV)
■ निम्न मद में सरकारी बजट के गैर-योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है–	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता	SSC CHSL (Tier-1) – 08/08/2023 (Shift-IV)
■ सरकारी बजट के स्थायित्वकारी कार्य में मुख्य रूप से _____ शामिल होता है–	मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए हस्तक्षेप	SSC CHSL (Tier-1) – 08/08/2023 (Shift-II)

■ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषण, केन्द्रीय बजट में की गई थी— 2021-22	SSC CGL (Tier-I) – 19/07/2023 (Shift-IV)
■ भारत सरकार ने पहली बार अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल किया— 2005-06	SSC CHSL (Tier-I) – 14/08/2023 (Shift-II)
■ सरकारी बजट के कार्यों में से एक है— आय और संपत्ति का पुनर्वितरण	SSC CHSL (Tier-I) – 09/08/2023 (Shift-III)
■ केन्द्रीय बजट 2023-24 में, भारत सरकार ने _____ योजना के तहत 500 नए 'अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है— गोबरधन	SSC CHSL (Tier-I) – 09/08/2023 (Shift-III)
■ वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है— आकस्मिक निधि, लोक लेखा और संचित निधि	SSC MTS/Havaldar– 11/07/2022 (Shift-III)
■ पूँजी बजट का एक घटक है— गैर-योजनागत पूँजीगत व्यय	SSC MTS/Havaldar– 06/07/2022 (Shift-II)
■ भारत का केन्द्रीय बजट सर्वोधिक बार प्रस्तुत किया है— मोरार जी देसाई ने	SSC MTS 05/08/2019 (Shift-I)
■ यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में परिवर्तन होगा— 100% बढ़ जाएगा	SSC CHSL (Tier-I) – 03/08/2023 (Shift-IV)
■ स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे— आर.के. शानमुखम चेट्टी	SSC MTS 13/10/2021 (Shift-II)
■ एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा— सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करके	(SSC 10+2 CHSL 30.01.17, 4.15 pm)
■ भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है— मुख्य आर्थिक सलाहकार	SSC MTS 09/08/2019 (Shift-III) SSC CGL (TIER-1) 27-10-2016, 1.15 pm
■ राजस्व प्राप्तियाँ और नॉन-डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट (NDCR) के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है— राजकोषीय घाटा	SSC MTS 06/10/2021 (Shift-III)
■ राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को _____ प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है— कर राजस्व	SSC MTS 27/10/2021 (Shift-I)
■ राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से _____ के विचारों पर आधारित है— जॉन मेनार्ड कीन्स	SSC CHSL 09/08/2021 (Shift-I)
■ यह उस समय होता है, जब मौजूदा खर्च, मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है— बजट घाटा	SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-II SSC CGL (Tier-I) – 10/06/2019 (Shift-I)
■ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है— राजकोषीय घाटा	SSC GD 25/11/2021 (Shift-I) SSC MTS 02/08/2019 (Shift-II)
■ भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया था— 1950-51	SSC GD 26/11/2021 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 03/03/2020 (Shift-III)
■ जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति कहलाती है— विस्तारवादी राजकोषीय नीति	SSC GD 24/11/2021 (Shift-II)
■ सरकार द्वारा ऋण का भुगतान, का एक उदाहरण है— पूँजीगत व्यय	SSC CHSL 31/05/2022 (Shift-II)
■ सरकार बजट घाटे के वित्तपोषण के लिए उधार ले रही है, का असर होगा— ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा	(SSC 10+2 CHSL 21.01.17, 4.15 pm)
■ सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है— सुरक्षा सम्बन्धी खर्चे	(SSC 10+2 CHSL 10.01.17, 1.15 pm)
■ भारत में सून्य आधारित बजट पहली बार प्रयोग किया गया था— 1987	SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-I)
■ केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है— आर्थिक मामलों के विभाग	SSC JE Civil - 23/01/2018 (Shift-I)
■ केंद्रीय बजट 2019-20 (Union Budget 2019-20) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक \$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है— 2024-25	SSC JE Civil 30.10.2020 (Shift-I)
■ केंद्र सरकार की गैर-योजना व्यय का अंग नहीं है— विद्युतीकरण पर खर्च	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-II)
■ भारत के बजट में, घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है— राजकोषीय घाटा	SSC JE Civil - 25/01/2018 (Shift-II) SSC JE Civil - 25/01/2018 (Shift-II) SSC MTS 02/08/2019 (Shift-III) SSC CGL (TIER-1) 11-09-2016, 4.15 pm SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-I)

राजस्व एवं राजकोषीय नीति/घाटा

■ सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है-	GST से	UDA/LDA 29-11-2015
■ एक गैर-योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है-	ब्याज का भुगतान	राजस्व निरीक्षक - 17-07-2016 (Paper-I)
■ राजस्व व्यय का एक उदाहरण है-	एक प्रिंटर की मरम्मत	लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है-	1 अप्रैल- 31 मार्च	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date: 17/07/2022
■ '14वें वित्त आयोग' के अध्यक्ष थे-	वाई.वी. रेड्डी	जूनियर इंजीनियर/तकनीकी- 31-07-2016
■ MPC के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है-	निवेश गुणक	RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-III)
■ किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है-	संपत्ति कर	RRB Group-D : 13/09/2022 (Shift-I)
■ कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ कहलाता है-	असामान्य लाभ	RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-I)
■ MPC (सीमांत उपभोग प्रवृत्ति) मान सामान्यतः-	1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है	RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-II)
■में जी.डी.पी. (GDP) वृद्धि दर, केन्द्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और वाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है-	समस्ति अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण	RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-III)
■ वह सरकारी संगठन जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है-	सेबी	RRB NTPC 10.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है-	राजस्व प्राप्ति	RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-I)
■ भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होता है जब-	राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है	RRB Group-D : 30/08/2022 (Shift-I)
■ प्राथमिक घाटे के बराबर होता है-	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान	RRB Group-D : 30/08/2022 (Shift-II)
■ सरकार की नीति है-	राजकोषीय नीति	RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift-I)
■ सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है-	कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण सूजक पूंजीगत प्राप्तियां)	RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-III)
■ सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है-	राजस्व घाटा	RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-III)
■ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष में एन.के सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया-	2016	RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-III)
■ सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है-	राजस्व घाटा	RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-I)
■ राजस्व व्यय का उदाहरण है-	सरकारी कर्मचारियों का वेतन	RRB Group-D – 20/09/2022 (Shift-I)
■ विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद अनुदान सहायता एक हिस्सा है-	राजस्व प्राप्ति का	RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-III)
■ तब होती है, जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है-	राजकोषीय तटस्थिता	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-II)
■ सरकारी घाटे (government deficit) को करों को या व्यय को कम किया जा सकता है-	बढ़ाकर; घटाकर	RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I)
■ राजकोषीय घाटे की परिभाषा है-	ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-III) RRB NTPC 12.01.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ ‘वित्तीय घाटा’ शब्द भारत सरकार के मंत्रालय से संबंधित है-	वित्त	RRB Group-D 31-10-2018 (Shift-I)
■ सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है-	राजस्व विभाग	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है-	राजकोषीय नीति	UPSI 14.11.2021 Shift-II
■ नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में शामिल होता है-	राजकोषीय प्रोत्साहन	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ सरकारी खर्च के स्रोत हैं-	ऋण का विस्तार	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ यदि कोई भी देश व्यापार घाटे में है, तो इसका मतलब होता है-	देश के घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे हैं	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017
■ जी.एस.टी. परिषद् का अध्यक्ष है-	केन्द्रीय वित्त मंत्री	UPPSC GIC 2021 UPPSC AW 2021
■ वह वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है-	लैफर वक्र	UPPCS (J) 2023
■ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य हैं-	राजकोषीय नीति के	ACF/RFO (Mains) IIInd 2018
■ संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद आयः होती है-	राज्यों को अनुदान	BEO Re-exam-2006-I
■ भारत में प्रत्यक्ष कर कोड सम्बन्धित है-	आय कर से	UPPCS (Pre) 2018
■ जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, तो उसे कहते हैं-	राजस्व घाटा	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है-	पूर्ण रोजगार	UPPCS (Pre) G.S. 2006
■ केन्द्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद है-	ब्याज भुगतान	UPPCS (Pre.) G.S. 1999
■ वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम (आउटकम) बजट का विचार लागू किया है। इसके अन्तर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व होगा-	वित्त मंत्रालय और योजना अयोग का संयुक्त रूप से	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2009
■ भारत में सकल घरेलू बचतों का सवाधिक हिस्सा है-	भौतिक परिसम्पत्तियों का	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2009
■ “लेखानुदान” संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है- निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2004
■ भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी-	वी. पी. सिंह द्वारा	UP RO/ARO (Pre) G.S. 2014
■ मुद्रा स्फीति की दरें आधारित होती हैं-	थोक मूल्य सूचकांक पर	UP Lower (Pre) Spl. G.S. 2004
■ भारतीय आयकर अधिनियम की धारा-88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है-	केलकर समिति ने	UPPCS (Pre.) G.S. 2016
■ भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है-	मार्ग कर (टोल टैक्स)	UPPCS (Pre) G.S. 2013
■ ‘मोडवेट’ सम्बन्धित है-	मूल्यवर्धित कर (वैट) से	UPPCS (Pre) GS 2011
■ भारत में पहली बार ‘व्यय कर’ लगाने का सुझाव दिया था-	कॉल्डर ने	UPPCS (Pre) GS 2010
■ वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किन्तु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है- कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर		UPPCS (Pre) G.S. 2004
■ केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटा कर- 30% करने का सुझाव दिया है		UPPCS (Pre) G.S. 2004
■ भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है-	जी.एस.टी. (2019-20)	UPPCS (Pre) G.S. Spl. 2004
■ भारत में केन्द्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं-		UPPCS (Pre) G.S. 1995
■ जी.एस.टी. (18%), निगम कर (18%), आयकर (17%)		
■ खरीददारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता-	आयकर	UPPCS (Pre) G.S. 1995
■ अप्रत्यक्ष कर है-	बिक्री कर	UPPCS (Pre) G.S. 1993
■ केन्द्र सरकार नहीं लगाती है-	मनोरंजन कर (राज्यकर)	UPPCS (Pre.) G.S. 1992
■ वर्ष 2009-10 में संघ सरकार की कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा-	निगम कर (कॉर्पोरेशन टैक्स) (वर्तमान में जी.एस.टी. 33%)	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2009

■ प्रत्यक्ष कर है-	आयकर	UPPCS (Pre) G.S. 1991
■ 'वैट' लगाया जाता है- उत्पादन तथा अन्तिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर		UPPCS (Main) G.S. Ist 2012 UPPCS (Main) G.S. IIInd 2006
■ तेरहवें वित्त आयोग की संसुलियों के अन्तर्गत राज्यों की भागीदारी केन्द्रीय करों में न्यूनतम होगी- 32 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 42 प्रतिशत)		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2009
■ भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है- राज्य सरकारों द्वारा		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2009
■ वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन था- निगम कर (जी.एस.टी. निगम कर 2019-20)		UPPCS (Main) Spl. GS IIInd 2008
■ राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है- निगम कर		UPPCS (Main) Spl. G.S. IIInd 2008
■ आयकर छूट नहीं है- यूनिट लिंकड इंश्योरेंस योजना पर		UPPCS (Main) G.S. Ist 2008
■ सेनेवैट (CENVAT) का सम्बन्ध है- केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
■ केन्द्र को वर्ष 2007-08 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई- निगम कर से (वर्तमान GST से)		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2006
■ निगम क्षेत्र की आय से सम्बन्ध नहीं है- सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2005
■ केवल संघीय सरकार के लिए होता है- सीमा शुल्क, निगम कर		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2005
■ एक कर समूह जो केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र किये जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है- उत्पादकर, आय पर उपकर, टटकर		UPPCS (Main) G.S. Ist 2003, 04
■ प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात है- राजकोषीय घाटा का		UPPCS (Pre) 2008
■ प्रत्यक्ष कर है- सम्पदा कर		UP RO/ARO (Pre) G.S. 2014
■ वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किन्तु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है- कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर		UP UDA/LDA (Pre) G.S. 2006
■ वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था- सामूहिक कर। (वर्तमान में जी.एस.टी.)		UP Lower (Pre.) G.S. 2015
■ स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल (सीवरेज) का वित्तपोषण जिस राजस्व से होगा, वह है- सम्पत्ति कर		UP Lower (Pre.) G.S. 2015
■ 'स्वच्छ भारत' कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार ने 6 नवम्बर, 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर है- 0.50 प्रतिशत		UP Lower (Pre.) G.S. 2015
■ यदि प्राथमिक घाटे में व्याज भुगतान को सम्प्रिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है- राजकोषीय घाटे के		UPPCS (Pre) GS 2010
■ हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद रहा है- व्याज की अदायगी		UPPCS (Pre) G.S. 2009 UPPCS (Pre) G.S. 2005
■ भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम होती है- आगम (रेवेन्यु) व्यय		UPPCS (Pre) G.S. 2006
■ आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है- सीमा कर के नाम से		UPPCS (Pre) G.S. 2006
■ भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है- राजकोषीय घाटा		UPPCS (Pre.) G.S. 2002 UPPCS (Main) G.S. IIInd 2004
■ वर्ष 2000-01 में केन्द्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया- 5.1% पर (वर्ष 2022-23 में 6.4%)		UPPCS (Pre.) G.S. 2000
■ वर्ष 1995-96 में केन्द्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पाद कर का योगदान था- 42% (वर्ष 2019-20 में 25%)		UPPCS (Pre.) G.S. 1997
■ वर्ष 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है- सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%		UPPCS (Pre) G.S. 1996
■ संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है- ऊर्जा पर		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2011
■ 13 फरवरी, 2014 को लगातार छठवीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया- जम्मू तथा कश्मीर ने		UPPCS (Main) G.S. Ist Paper 2013
■ समयावधि 2008-10 के मध्य केन्द्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है- व्याज भुगतान		UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2010

■ संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है— (वर्ष 2019-20 में जीडीपी का 3.3%)	जीडीपी का 5.5%	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
■ यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा— सकल प्राथमिक घाटा		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
■ बागहवें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केन्द्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिये— शून्य%		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
■ राजस्व घाटे की अपेक्षा, राजकोषीय घाटा सदैव— अधिक रहेगा		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
■ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था— 2003 में		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
■ संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है— घरेलू उधारों से		UPPCS (Main) G.S. IIInd 2005
■ भारतीय केन्द्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है— प्राथमिक घाटा		UPPCS (Main) Spl. G.S. IIInd 2004
■ 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कम्पनियों की अंशपूँजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है— 49% (वर्तमान में 74%)		UP RO/ARO (Pre) G.S. 2014
■ बागहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के बाँटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है— 30.5 (चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार 42%)		UPPCS (Pre) G.S. 2006
■ वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है— तट कर		UPPCS (Pre.) G.S. 2000
■ वित्त आयोग का मुख्य कार्य है— करों का राज्य व केंद्र में बंटवारा करना		UPPCS (Pre.) G.S. 1993
■ भारत के तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है— जनसंख्या पर। (14वें में भी 50%)		UPPCS (Main) G.S. II nd 2011
■ वित्त आयोग का गठन किया जाता है— 5 वर्ष की अवधि के लिए		UPPCS (Main) G.S. I st 2010
■ तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि रही— 2010-15		UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संस्तुति की गयी— 32.0% (14वाँ, 42%)		UPPCS (Main) G.S. Ist Paper 2009
■ 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा— 29.5%		UP Lower (Pre.) Spl. G.S. 2002
■ केन्द्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों की विवेचना की गयी है— अनुच्छेद 268-281 के अन्तर्गत		UPPCS (Pre) GS 2014
■ घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। परन्तु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति मुद्रास्फीति की		UPPCS (Pre.) G.S. 1993
■ “आर्थिक समीक्षा” को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व है— वित्त मंत्रालय का		UPPCS (Main) G.S. II nd 2010 UP UDA/LDA Spl. (Pre) G.S. 2010
■ सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा है— 2007-08 में (वर्तमान में 8.5%)		UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ वर्ष 2009-10 में सेवाएँ जो सेवा कर के दायरे में रहीं, की संख्या थी— 114		UPPCS (Main) G.S. II nd 2009
■ आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद है— ब्याज भुगतान		UPPCS (Main) Spl. GS II nd 2008
■ तेहरवें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केन्द्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए— 68%		UPPCS (Main) Spl. GS II nd 2008
■ सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 के पश्चात् ऋणात्मक रहने के उपरान्त धनात्मक हो गई— 2003-04 में		UPPCS (Main) G.S. II nd 2006
■ संघीय बजट 2005-06 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था— उत्पाद कर (वर्तमान में GST)		UPPCS (Main) G.S. I st 2005
■ आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है— आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व		UPPCS (Main) G.S. II nd 2004

■ चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया-	1994 से	UP UDA/LDA Spl. (Pre.) G.S. 2010
■ जिला सांख योजना बनायी जाती है-	लीड बैंक के अन्तर्गत	UP Lower (Pre.) Spl. G.S. 2002
■ उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई-	प्रधानमंत्री नरसिंहा राव द्वारा	UPPCS (Pre) GS 2013
■ सेवा कर है-	प्रत्यक्ष कर	UPPSC AE- 2007 Paper (I)
■ सट्टे द्वारा पूँजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य है-	टोबिन टैक्स	UPPSC AE-2008
■ वह कर जो केन्द्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा केन्द्र और राज्यों में बाँटे नहीं जाते हैं-	आयात-निर्यात कर एवं निगम कर	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ मॉडवेट योजना का उद्देश्य है-	कच्चे माल के स्तर से लगा कर अन्तिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ एक अप्रत्यक्ष कर है-	वस्तु एवं सेवा कर	SSC CGL (Tier-II) – 03/03/2023
■ डिजिटल परिसंपत्तियों पर आयकर के अलावा, _____ टीडीएस और उपहार कर भी होगा, जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर किया जाएगा-	1%	SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-I)
■ भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है-	केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल	SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-III)
■ बजट 2022 की घोषणा के अनुसार, क्रिएटोरेंसी जैसी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से होने वाली आय पर आयकर लगाया जाएगा-	30%	SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के _____ संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया-	101वें	SSC CGL (Tier-I) 19/04/2022 (Shift-III) SSC JE Electrical 29.10.2020 (Shift-II)
■ वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ		SSC CHSL (Tier-1) – 14/08/2023 (Shift-II)
■ जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुँच जाती है, तो कथन सही होगा-	अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे	SSC CHSL (Tier-1) – 02/08/2023 (Shift-I)
■ बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर है-	निवल अप्रत्यक्ष कर	SSC CHSL (Tier-1) – 11/08/2023 (Shift-III)
■ प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है-	आयकर	SSC CHSL (Tier-1) – 17/08/2023 (Shift-II)
■ किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है-	उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय	SSC CGL (TIER-1) 11-09-2016, 1.15 pm
■ वित्त मंत्रालय ने निम्न के लिए फॉर्म 26 AS नामक नया फॉर्म प्रस्तावित किया है-कर-दाताओं		SSC CHSL 06/08/2021 (Shift-III)
■ भारत में मूल्य वर्धित कर लाया गया था-	2005 में	SSC MTS 08/10/2021 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) – 04/06/2019 (Shift-I)
■ इस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है-	निर्मित उत्पाद	SSC GD 18/02/2019 (Shift-I)
■ Octroi है-	टैक्स	SSC CGL (TIER-1) 08-09-2016, 4.15 pm
■ निम्न कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है-	माल और सेवा कर	SSC JE Civil 30.10.2020 (Shift-I) SSC CPO-SI 24/11/2020 (Shift-I)
■ वस्तु या सेवा पर जीएसटी (GST) लागू नहीं है-	शराब	SSC MTS 08/08/2019 (Shift-III)
■ निम्न कर को, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है-	सेक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स	SSC JE Electrical 29.10.2020 (Shift-II)
■ निम्न करों का समुच्चय केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध है- उत्पाद कर, सीमा शुल्क व आयकर		SSC CGL (TIER-1) 09-09-2016, 4.15 pm SSC CGL (TIER-1) 04-09-2016, 4.15 pm SSC CGL (TIER-1) 27-08-2016, 4.15 pm SSC CGL (TIER-1) 27-10-2016, 1.15 pm
■ सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान इसके द्वारा किया जाता है-	दर्शक द्वारा	SSC JE Civil - 24/01/2018 (Shift-II)

■ निम्न कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी—	प्रगामी कर	SSC CGL 03-09-2016, 1.15 pm
■ ‘सेनेट’ संबंधित है—	उत्पाद शुल्क	SSC CGL 08-09-2016, 10 am
■ प्रत्यक्ष-कर का मुख्य रूप से प्रभाव पर पड़ता है—	आय पर	SSC CGL (TIER-1) 10-09-2016, 1.15 pm
■ सीमा शुल्क सरकार की नीतियों का एक साधन है—	राजकोषीय	(SSC 10+2 CHSL 31.01.17, 1.15 pm)
■ एक प्रत्यक्ष कर है—	संपत्ति कर	(SSC 10+2 CHSL 25.01.17, 10 am)
■ भारत में निम्न एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं— एंटी डंपिंग इयूटी		(SSC 10+2 CHSL 16.01.17, 1.15 pm)
■ मूल्यवर्धित कर को लागू किया जाता है—	मूल्य पर	(SSC 10+2 CHSL 16.01.17, 1.15 pm)
■ यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता—	प्रत्यक्ष कर	(SSC 10+2 CHSL 16.01.17, 1.15 pm)
■ जीएसटी के संदर्भ में, तथ्य सही है—जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है		SSC CPO-SI – 11/12/2019 (Shift-II)
■ निम्न को ‘पिगोवियन कर’ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है— कार्बन कर (टैक्स)		SSC CPO-SI – 12/12/2019 (Shift-II)
■ सुगम कर — से संबंधित है—	आयकर	SSC GD 11/03/2019 (Shift-II)
■ वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत — बन गया है— एक सामान्य बाजार		SSC GD 09/03/2019 (Shift-II)
■ कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिन्हें सम्मिलित रूप से — के रूप में जाना जाता है— वित्तीय नीति		SSC CPO-SI 24/11/2020 (Shift-II)
■ जीएसटी (GST) परिषद में सदस्य हैं—	33	SSC MTS 02/08/2019 (Shift-II)
■ जी. एस. टी. (GST) परिषद् द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जी.एस.टी. (GST) दर है—	28%	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 03/03/2020 (Shift-I)
■ भारत का प्रमुख राज्य कर है—	स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण	SSC CHSL (Tier-I) – 11/07/2019 (Shift-III)
■ सकल राजकोषीय घाटा—	कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)	(SSC J.E. 04.03.17, 2:45 pm) (SSC J.E. 04.03.17, 10:00 am) SSC CGL (Tier-I) – 07/06/2019 (Shift-II)
■ पूँजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है—	राजकोषीय घाटा	SSC CGL (Tier-I) – 12/06/2019 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I) – 12/06/2019 (Shift-II)
■ सीमांत राजस्व है—	अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को	SSC CPO (TIER-1) 2016

मुद्रा एवं बैंकिंग/वित्तीय समावेशन की योजनाएँ

■ भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था—	वर्ष 1976 में	RRB Group-D 22/08/2022 (Shift-I)
■ कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तपोषण करने वाली एक केन्द्रीय या शीर्ष संस्था है—	नाबांड	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-II
■ वह संगठन जो भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएँ तैयार करता है— नाबांड		UDA/LDA 29-11-2015
■ वह अधिनियम जिसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित कीं— बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण)	अधिनियम, 1970	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-I
■ एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है—	सिडबी	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-I
■ वह संस्था जो भारत में मौद्रिक नीति बनाती है—	आरबीआई	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022
■ सौ रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है—	आर.बी.आई. गवर्नर द्वारा	UPSSSC PET 24/08/2021 Sift-I
■ यदि आर. बी.आई. नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर असर होगा—	बढ़ जायेगी	UPSSSC PET 24/08/2021 Sift-I

■ बैंक दर का अर्थ है-	देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक व्याज दर	UPSSSC PET 24/08/2021 Shift-I
■ दस रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है-	RBI गवर्नर	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ भारत में वह बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है-	फेडरल बैंक लि.	UPSSSC Computer Operator 10/01/2020 RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-I)
■ वह बैंक जिसने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी-	ICICI बैंक	UPSSSC Homeopathic Pharmacist 24/10/2019
■ एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है-	10	लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ आयात निर्यात (एग्जिम) बैंक स्थापित हुआ था-	1982 में	लोअर द्वितीय- 06-03-2016 जूनियर इंजीनियर/तकनीकि - 27-12-2015 RRB NTPC 27.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ एक सामान्य बही खाता जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है-	वास्तविक खाता	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift - II)
■ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	परिचालक - 23-08-2015
■ ‘द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया’ को राष्ट्रीयकरण के पश्चात् नाम दिया गया-	भारतीय स्टेट बैंक	UDA/LDA 29-11-2015
■ भारत में, कृषि और संबंधित क्रियाकलापों कोके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है-	वाणिज्यिक बैंक	UDA/LDA 29-11-2015
■ मुद्रा का तात्पर्य होता है-	मूल्य का मापक	बन रक्षक - 11-12-2015
■ एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं-	वित्त सचिव के	जूनियर इंजीनियर/तकनीकि - 27-12-2015
■ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई है-	अप्रैल, 1935 में	ग्राम पंचायत अधिकारी- 21-02-2016 RRB Group-D 29-10-2018 (Shift-III) RRB NTPC 29.03.2016 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 23.07.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 01.04.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 15.11.2021 Shift-III UPSI 21.11.2021 Shift-I UPP Constable, 25.10.2018 UPPSC AE-2004
■ वह प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी जो भारत में अगस्त, 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई-	बंधन बैंक	लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ एक द्रवता अनुपात है-	चालू अनुपात	लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है-	सिक्किम	लोअर द्वितीय- 06-03-2016
■ वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण मेंबैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ-	6	लोअर द्वितीय- 06-03-2016
■ डिजिटल मुद्रा का एक रूप है-	बिटक्वाइन	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-II)
■ संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक (निरस्त और संशोधन) विधेयक 2017 पारित किया है-	6	विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift - I)
■ नाबार्ड (NABARD) का विस्तृत रूप है-	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट	ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- I)

■ स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास हुआ—	1978 ई. में	स्टेनोग्राफर - 10-03-2019
■ वह अधिनियम जिसमें एक ऐसा प्रावधान है, जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है—	आर बी आई अधिनियम की धारा 7	स्टेनोग्राफर - 10-03-2019
■ आर.बी.आई. की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था—	कोलकाता में	कनिष्ठ सहायक - 19-02-2019
■ भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार के पास है—	भारत सरकार	ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- II)
■ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है—	बैंकिंग लोकपाल	ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- II) RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के पुनर्जीकरण की योजना को तक विस्तार की मंजूरी दे दी है—	वर्ष 2020 में	ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- I)
■ वह बैंक जिसके द्वारा 'सिम्पली क्लिक' क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है—	S.B.I.	जूनियर इंजीनियर/तकनीकी- 31-07-2016
■ "पूर्ति अपनी माँग का सृजन स्वयं करती है।" यह कथन है—	जे.बी.से.का	चकबन्दी लेखपाल - 08-11-2015 (Morning)
■ उत्पादन लागत में शामिल उपरि व्यय (overhead expense) है—	बीमा	RRB Group-D : 29/08/2022 (Shift-II)
■ सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है—	आईसीआईसीआई	RRB NTPC 25.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत में माइक्रोफाइनेंस, वित्तीय सेवा का वह रूप है, जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है—	लघु अवधि	RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift-III)
■ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है—	माइक्रोफाइनेंस पत्प	RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-III)
■ वर्ष 2016 में, विमुद्रीकरण के बाद छापी गई महात्मा गांधी शृंखला की नई नोटों में से मूल्यवर्ग के नोट पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित है—	2000 रु. (फिलहाल 2000 का नोट बंद)	RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-II)
■ वह योजना जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है—	प्रधानमंत्री जन धन योजना	
■ 2010 में AP माइक्रोफाइनेंस संकट के मद्देनजर, RBI ने MFI क्षेत्र में मुद्रा और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था—	वाई.एच.मालेगाम	RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है—	सोनाली बैंक लिमिटेड	RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-III)
■ कोलकाता में स्थित सूक्ष्म, ऋणदाता, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए RBI द्वारा सेंद्रीयिक मंजूरी प्रदान की गई थी—	वर्ष 2014 में	RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-III)
■ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का मुख्यालय स्थित है—	मुंबई में	RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय मुद्रा प्रणाली में को अन्तिम ऋणदाता कहा जाता है— भारतीय रिजर्व बैंक		RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-I)
■ मुद्रा आपूर्ति/पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है—	M3	RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-II)
■ बंधन बैंक की स्थापना हुई थी—	वर्ष 2015 में	RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-III)
■ बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय है, जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है—	कोलकाता	RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-I)

■ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है-	SIDBI	RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-III)
■ M3 (अर्थात् मुद्रा आपूर्ति का माप) की गणना के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है— $M3 = CU + DD + \text{वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा राशि}$		RRB Group- D – 20/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचा जारी किया था— वर्ष 2011 में		RRB Group- D – 20/09/2022 (Shift-II)
■ सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में हो रहा है— शांतिवादी		RRB Group- D – 25/08/2022 (Shift-II)
■ पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्मस (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया— वर्ष 2020 में		RRB Group- D – 28/09/2022 (Shift-III)
■ भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) का निर्धारण किया जाता है— आरबीआई (RBI) द्वारा		RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-I)
■ किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है, वह शब्द है— साख रेटिंग		RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी से प्रभावी हुआ— 1949		RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)
■ भारत में साख नियंत्रण (Credit Control) का कार्य करती है— भारतीय रिजर्व बैंक		RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III)
■ भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है— यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है		RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-III)
■ जुलाई 2019 में, उस समय के सबसे बड़े NBFC-MFI का इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया— भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड		RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-III)
■ बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे— महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय		RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-II)
■ वह संस्थान जिसने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रोफाइनेंस गतिविधि शुरू की थी— नाबार्ड (NABARD)		RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-III)
■ मुद्रा का प्राथमिक कार्य है— यह विनियम का माध्यम है		RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-I)
■ 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रोफाइनेंस संस्थान था— बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-I)
■ NBFC(एनबीएफसी) का पूर्ण रूप है— नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी		RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-II)
■ आरक्षित नकदी निधि अनुपात है— वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई (RBI) के पास रखना होता है		RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-II)
■ MUDRA का पूर्ण रूप है— Micro Units Development and Refinance Agency		RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-II)
■ वह पशु जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिह्न पर मौजूद है— बाघ		RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-III)
■ शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था— वर्ष 2018 में		RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-I)
■ भारत में पहली माइक्रो-फाइनेंस पहल थी— सेवा (SEWA) बैंक		RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift - II)
■ भारत का वह माइक्रोफाइनेंस संस्थान जो केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है, और विदेशी मुद्रा विनियम सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा, एवं पर्यटन प्रदान करता है— मुथूठ फाइनेंस लिमिटेड		RRB Group-D – 24/08/2022 (Shift-II)